

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-02

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

*2. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार, कितने गांवों में विद्युत उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गाँवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 02 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : विगत दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गाँवों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) और (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे। गैर-विद्युतीकृत 18,452 गाँवों में से 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, 7,108 गैर-विद्युतीकृत गाँवों में विद्युतीकरण-कार्य पूरा कर दिया गया है। शेष सभी गाँवों का विद्युतीकरण 01 मई, 2018 तक कर दिए जाने का लक्ष्य है।

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 02 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

विगत दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	2014-15	2015-16
1	अरुणाचल प्रदेश	107	174
2	असम	190	942
3	बिहार	341	1754
4	छत्तीसगढ़	67	405
5	हिमाचल प्रदेश	8	1
6	जम्मू व कश्मीर	9	27
7	झारखंड	161	750
8	मध्य प्रदेश	86	214
9	मणिपुर	192	75
10	मेघालय	43	1
11	मिजोरम	45	16
12	नागालैंड	10	0
13	ओडिशा	13	1264
14	राजस्थान	70	163
15	त्रिपुरा	0	9
16	उत्तर प्रदेश	59	1305
17	उत्तराखंड	4	0
18	पश्चिम बंगाल	0	8
	कुल	1405	7108

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-06

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाली तथा लाभकर इकाइयों
को बिजली की आपूर्ति

*6. डॉ. वी. मैत्रेयन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाली तथा लाभकर इकाइयों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने विधिवत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन की निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पी.ए.टी.) योजना के अंतर्गत अधिक ऊर्जा की खपत करने वाले आठ क्षेत्रों की 478 औद्योगिक इकाइयों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत (एस.ई.सी.) को कम करने के संबंध में मानक निर्धारित किए हैं;
- (घ) यदि हां, तो इन इकाइयों द्वारा ऊर्जा की खपत में कमी करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को, राज्य-वार, कहां तक हासिल कर लिया गया है; और
- (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में औद्योगिक इकाइयों को कुल कितने मूल्य के ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाली तथा लाभकर इकाइयों को बिजली की आपूर्ति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 06 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाली तथा लाभकर इकाइयों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों तथा पारेषण प्रणालियों की स्थापना कर राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। पीएटी चक्र-1 (2012-13 से 2014-15) में 478 औद्योगिक इकाइयों को विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) में कमी करने के लिए अनिवार्य लक्ष्य दिए गए थे। इसका उद्देश्य समग्र ऊर्जा खपत में 6.686 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) कमी हासिल करना था।

इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा 8.67 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) कमी करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया। यह कमी लाने के लिए प्राप्त समग्र लक्ष्य के राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ड) : पीएटी चक्र-1 (2012-13 से 2014-15) के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को जारी किए जाने वाले ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्रों का कुल अनुमानित मूल्य 37.60 लाख ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ईएससर्ट्स) है।

"अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाली तथा लाभकर इकाइयों को बिजली की आपूर्ति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 06 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	ऊर्जा बचत (एमटीओई)
1	आंध्र प्रदेश	0.38
2	असम	0.06
3	बिहार	0.03
4	छत्तीसगढ़	0.65
5	दिल्ली	0.07
6	गोवा	0.03
7	गुजरात	0.88
8	हरियाणा	0.41
9	हिमाचल प्रदेश	0.05
10	झारखंड	0.63
11	कर्नाटक	0.36
12	केरल	0.01
13	मध्य प्रदेश	0.75
14	महाराष्ट्र	0.72
15	मेघालय	0.01
16	ओडिशा	1.04
17	पुडुचेरी	-0.01
18	पंजाब	0.45
19	राजस्थान	0.62
20	तमिलनाडु	0.22
21	तेलंगाना	0.05
22	त्रिपुरा	0.00
23	उत्तर प्रदेश	0.74
24	उत्तराखंड	0.05
25	पश्चिम बंगाल	0.48
	कुल	8.67

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-15

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

देश में मांग की तुलना में विद्युत उत्पादन

*15. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में विद्युत उत्पादन की तुलना में इसकी मांग कितने मेगावाट है;

(ख) क्या मंत्रालय बिजली की कमी को पूरा करने के लिए विशेषकर पर्वतीय राज्यों में जलविद्युत का उत्पादन बढ़ाने पर विचार करेगा;

(ग) क्या सरकार छोटे-छोटे बांध बनाकर जलविद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध करायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो बिजली की बढ़ती मांग को कैसे पूरा किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"देश में मांग की तुलना में विद्युत उत्पादन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : वर्ष 2015-16 (अप्रैल, 2015-मार्च, 2016) के दौरान देश में मेगावाट में विद्युत की व्यस्ततम माँग 148,463 मेगावाट की पूरी की गई माँग (अर्थात् सकल उत्पादन, सहायक खपत एवं पारेषण हानियाँ को घटाकर) की तुलना में 153,366 मेगावाट थी।

(ख) : जी, हाँ।

(ग) और (घ) : जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यों को निधि उपलब्ध कराने हेतु फिलहाल कोई स्कीम/नीति नहीं है।

सरकार द्वारा विद्युत की माँग को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् वर्ष 2016-17 तक, 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि। इसकी तुलना में 31 मार्च, 2016 तक पारंपरिक स्रोतों से लगभग 85,186 मेगावाट तथा 31.03.2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से 17,829 मेगावाट क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।

(ii) भारत सरकार ने राज्यों के साथ भागीदारी से 24x7 सभी के लिए विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए पहल की है।

(iii) भारत सरकार द्वारा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने तथा लाइन हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण तथा कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमों अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(iv) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य माँग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।

(v) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नअराउंड के लिए 20 नवम्बर, 2015 को एक नई स्कीम अर्थात् उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

(vi) उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाएं शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का तेजी से समाधान करना।

(vii) स्ट्रैंडेड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता प्रदान कराना।

(viii) सिक्किम सहित सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए 9865 करोड़ रुपए की दो स्कीमों कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(ix) जम्मू एवं कश्मीर में कमी को पूरा करने में सहायता प्रदान करने हेतु कुल 1788 करोड़ रुपए की 220 केवी श्रीनगर से लेह वाया ट्रांस, कारगिल लाइन भारत सरकार के वित्तपोषण से कार्यान्वित की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-66

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

एलईडी बल्बों के वितरण में अनियमितताएं

66. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या विद्युत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एलईडी बल्बों के वितरण में सरकार को बड़े पैमाने पर अनियमितताएं नजर आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या जनता को एलईडी बल्बों की आपूर्ति के संबंध में राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं में काफी अंतर है;
- (ग) क्या सरकार वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई जांच शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या मंत्रालय को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-67

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि हेतु मुआवजा

67. श्री किरनमय नन्दा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी विद्युत परियोजनाओं के लिए किसानों से अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ताप/जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किसानों में अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। समय-समय पर संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि हेतु राज्य सरकार द्वारा सीधे भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी)के साथ-साथ ताप/जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में भू-स्वामियों को भुगतान किए गए मुआवजे के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन/परियोजना का नाम	अधिगृहीत निजी भूमि	भू-स्वामियों को किया गया भुगतान (रुपए करोड़ में)
1	चूटक (44 मेगावाट), (जम्मू व कश्मीर)	18.63 हेक्टे.	2.23
2	निम्मो-बाजगो (45 मेगावाट) (जम्मू व कश्मीर)	31.27 हेक्टे.	6.40
3	उरी-II (240), (जम्मू व कश्मीर)	150.10 हेक्टे.	27.11
4	किशनगंगा (330 मेगावाट), (जम्मू व कश्मीर)	255.00 हेक्टे.	271.84
5	सेवा-II (120 मेगावाट), (जम्मू व कश्मीर)	66.10 हेक्टे.	4.77
6	पारबती-III (520 मेगावाट), (हिमाचल प्रदेश)	46.00 हेक्टे.	66.0
7	चमेरा-III (231 मेगावाट), (हिमाचल प्रदेश)	4.23 हेक्टे.	1.16
8.	पारबती-II (800 मेगावाट), (हिमाचल प्रदेश)	52.73 हेक्टे.	24.95
9.	कोटलीभेल-1ए (195 मेगावाट), (उत्तराखंड)	18.65 हेक्टे.	7.17
10	नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन (1500 मेगावाट), (हिमाचल प्रदेश)	224.00 हेक्टे.	27.12
11	रामपुर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (420 मेगावाट), (हिमाचल प्रदेश)	29.10 हेक्टे.	24.18
12	नटवर मोरी एचईपी (60 मेगावाट), (उत्तराखंड)	7.156 हेक्टे.	11.01
13	बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1360 मेगावाट), (बिहार)	436.60 हेक्टे.	357.00 मुआवजा संवितरण प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है। लगभग 90% मुआवजा संवितरित।
14	टांडा, (2x660 मेगावाट), (उत्तर प्रदेश)	671.99 एकड़	189.84
15	बिल्हौर, (2x660 मेगावाट), (उत्तर प्रदेश)	950.52 एकड़	372.23
16	गदरवाड़ा, (2x800 मेगावाट), (मध्य प्रदेश)	1479.48 एकड़	80.25
17	खारगोन, (2x660 मेगावाट), (मध्य प्रदेश)	783.78 एकड़	76.00
18	बरेठी, (4x660 मेगावाट), (मध्य प्रदेश)	2452.13 एकड़	111.87
19	दार्लीपल्ली, (2x800 मेगावाट), (ओडिशा)	1361.60 एकड़	348.73
20	कुडगी, (3x800 मेगावाट), (कर्नाटक)	3351.00 एकड़	248.00
21	लारा, (2x800 मेगावाट), (छत्तीसगढ़)	2383.26 एकड़	292.35
22	टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, उत्तराखंड	15000 परिवार	1526.00
23	विष्णुगाड़ पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट) उत्तराखंड	31.639 हेक्टे.	20.74
24	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट), बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	1360.00 एकड़	387.18
25	चेय्यूर यूएमपीपी (4000 मेगावाट), तमिलनाडु	655.15 एकड़	83.57
26	ओडिशा यूएमपीपी (4000 मेगावाट), ओडिशा	2733.00 एकड़	620.78 संवितरण के लिए भुगतान किया गया।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-68

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

देश के ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन

68. श्री रंजिब बिस्वाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सचिवों के समूह ने संरक्षण तथा दक्षता के जरिए भारत के ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए अनेक परिवर्तनकारी उपायों की सिफारिश की है;
- (ख) यदि हां, तो इस समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है तो प्रतिवर्ष कुल कितनी ऊर्जा को संरक्षित किए जाने की संभावना है; और
- (घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ।

(ख) : सचिव-समूह ने ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता के जरिए भारत के ऊर्जा संसाधनों का प्रबंध करने के लिए निम्नलिखित 11 सूत्रीय कार्य की सिफारिश की:

1. सुपर-एफिशिएंट हाउसहोल्ड एप्लायंसेज डिप्लायमेंट एंड नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इनिटिएटिव (शक्ति): सुपर एफिशिएंट हाउसहोल्ड उपकरणों की वर्तमान 10 प्रतिशत बिक्री को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना।
2. सोलर-बेस्ड एफिशिएंट वाटर-पम्पस फॉर एग्रीकल्चर (सेवा): वर्ष 2019 तक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य (एलईडी टाइप) व्यावसाय मॉडल के जरिए 30 लाख सौर आधारित ऊर्जा दक्ष वाटर पम्प प्रदान करना।

3. **ऊर्जा दक्ष (ईई) भवन एवं निर्माण सामग्री:** ऊर्जा प्रयोग को 25% तक घटाने के लिए, कम से कम 30% निर्माणों और मौजूदा सरकारी भवनों को शामिल करने के लिए नए ऊर्जा दक्ष भवनों को प्रोत्साहन देना।
4. **ऊर्जा गहन उद्योग:** औद्योगिक ऊर्जा खपत की कवरेज, जो वर्तमान में 30% है, को बढ़ाकर 70% किए जाने के लिए निष्पादन हासिल एवं व्यापार करो कार्यक्रम का विस्तार।
5. **परिवहन - सड़क:** दो चरणों में, 12-40 एमटी की रेंज में हैवी ड्यूटी वाहनों (एचडीवी) के लिए ईंधन दक्षता मानदंड अनिवार्य करना तथा सभी रेंजों में पुराने एचडीवी को प्रतिस्थापित करने को प्रोत्साहित करना।
6. **परिवहन - सड़क:** ईंधन दक्ष चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
7. **परिवहन - रेलवे:** माल-वहन में रेलवे के घटते हिस्से को नियंत्रित करना तथा वर्तमान 36 प्रतिशत को बढ़ाकर वर्ष 2019 तक 40 प्रतिशत तक करना।
8. **परिवहन - तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देना:** तटीय पोत परिवहन माल-वहन के हिस्से को बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक करना।
9. **नई प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकीकरण:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा विकसित सूक्ष्म सौर गुंबद (सूर्या ज्योति) प्रकाश-व्यवस्था प्रौद्योगिकी द्वारा सार्वभौमिक प्रकाश-व्यवस्था पहुँच।
10. **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास:** मिश्रण के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) ताप विद्युत प्रौद्योगिकी एवं लिग्नो-सेलुलॉसिक बायो-एथानॉल।
11. **ऊर्जा संरक्षण - एक जन आंदोलन:** ऊर्जा अभिनव पुरस्कार, जिला स्तरीय जागरूकता तथा यथार्थतः ऊर्जा दक्षता केंद्र।

(ग) : सिफारिशों के कार्यान्वयन से, वर्ष 2019 के अंत तक, 44 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) की बचत होने की संभावना है।

(घ) : माननीय विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के समक्ष सचिव-समूह की सिफारिशों पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया था जिसमें विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उप-सचिव एवं उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों तथा इनके साथ-साथ, इस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों ने भी भाग लिया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान, कार्य योजना तैयार करने के लिए, इन सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान किए गए विचार-विमर्श और प्राप्त सुझावों के आधार पर, कार्यान्वयन के लिए, समय-सीमा सहित एक कार्य योजना तैयार की गई है। यह कार्य योजना इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नीति-आयोग को भेज दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-69

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

यू एम पी पी हेतु नए मानक

69. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय सरकार देश की अति वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए नए मानक लागू करने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या ये मानक मौजूदा अति वृहद विद्युत परियोजनाओं पर भी लागू होंगे;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) अब तक आरंभ की जा चुकी अतिवृहद विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में निर्माणाधीन अन्य अतिवृहद विद्युत परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हां। पणधारकों द्वारा व्यक्त विभिन्न चिंताओं का समाधान करने और बोली प्रक्रिया में निवेशकों/उत्पादकों की अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी)/केस-2 के लिए लागू मानक/मॉडल बोली दस्तावेजों की जांच करने और संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने आबंटित घरेलू कोयला ब्लॉकों और आयातित कोयले के आधार पर अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए नए मानक बोली दस्तावेजों पर अपनी संस्तुति दे दी हैं। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, नए मानक बोली दस्तावेज अन्तिम अनुमोदनाधीन है।

(ग) और (घ) : जी नहीं, ये दस्तावेज उन यूएमपीपी के लिए लागू होंगे जिनके लिए बोली प्रक्रिया अभी शुरू की जानी है।

(ङ) : चालू/कार्यान्वयनाधीन यूएमपीपी का ब्यौरा अनुबंध में है।

राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	सासन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 07.08.2007 को अवार्ड एवं हस्तांतरित की गई। परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।
2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	ग्राम टुंडावंड, जिला कच्छ, गुजरात	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को 24.04.2007 को अवार्ड एवं हस्तांतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	कृष्णापटनम, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 29.01.2008 को अवार्ड तथा हस्तांतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर कार्य रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	तिलैया गाँव के निकट, जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 07.08.2009 को अवार्ड और हस्तांतरित की गई। विकासकर्ता (झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि.) ने झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का हस्तांतरण नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार की समाप्ति नोटिस जारी किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-70

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों को बंद किया जाना

70. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ ताप विद्युत संयंत्र, विशेषकर महाराष्ट्र में, बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ताप विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत की अबाधित आपूर्ति के लिए निरन्तर उत्पादन करने के लिए पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य विकल्पों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के बीड जिले में पार्ली ताप विद्युत स्टेशन (1130 मेगावाट) की सभी यूनिटें जून-जुलाई, 2015 से जल की कमी के कारण बंद हैं। यूनिटों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. यूनिट सं. 03 (210 मेगावाट) - 27 जून, 2015
2. यूनिट सं. 04 (210 मेगावाट) - 05 जुलाई, 2015
3. यूनिट सं. 05 (210 मेगावाट) - 06 जुलाई, 2015
4. यूनिट सं. 06 (250 मेगावाट) - 25 जून, 2015
5. यूनिट सं. 07 (250 मेगावाट) - 08 जुलाई, 2015

जल के उपलब्ध न होने के कारण अस्थायी रूप से बंद अन्य ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

महाजेनको ने सूचित किया है कि नांदेड बाघला शहर के नगर निगम से सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) जल के पुनः उपयोग परियोजना (60-एमएलडी) के माध्यम से पार्ली ताप विद्युत स्टेशन को जलापूर्ति किए जाने की स्कीम तैयार की जा चुकी है।

भारत सरकार ने दिनांक 28 जनवरी, 2016 को नई प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है जिसमें यह अधिदेशित है कि नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों/इसी प्रकार के संगठन के सीवेज उपचार संयंत्र के 50 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्र सीवेज उपचार संयंत्र से उनकी निकटता के क्रम में इन निकायों द्वारा उत्पादित उपचारित सीवेज का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा इस पर आई संबंधित लागत की अनुमति प्रशुल्क में पास-थ्रू के रूप में दी जाए।

राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उन ताप उत्पादक इकाइयों का आउटेज ब्यौरा जो कच्चे पानी की समस्या के कारण अस्थायी रूप से बंद थीं

क्षेत्र	राज्य	सेक्टर प्रकार	संगठन	स्टेशन	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	ट्रिप तारीख	सिंक्रो. तारीख	आउटेज के कारण
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	बाढ़-II	4	660	11-जुला.-15	11-जुला.-15	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटोक स्तर
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	बाढ़-II	5	660	4-अक्टू.-15	5-अक्टू.-15	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	1	200	1-अप्रैल-16	6-अप्रैल-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	2	200	1-अप्रैल-16	4-अप्रैल-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	3	200	1-अप्रैल-16	11-अप्रैल-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	4	500	15-फर.-16	18-फर.-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	4	500	1-अप्रैल-16	11-अप्रैल-16	कच्चे पानी की समस्या
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.	फरक्का एसटीपीएस	5	500	1-अप्रैल-16		कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	1	210	1-सितंबर-15	2-सितंबर-15	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	1	210	17-मार्च-16	21-मार्च-16	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटोक स्तर
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	2	210	15-मार्च-16	21-मार्च-16	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटोक स्तर
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	5	210	11-फर.-16	13-फर.-16	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	6	210	14-मार्च-16	20-मार्च-16	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटोक स्तर

दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	7	210	17-फर.-16	19-फर.-16	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	राज्य	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस	7	210	15-मार्च-16	21-मार्च-16	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
दक्षिणी क्षेत्र	तमिलनाडु	केंद्रीय	एनटीपीएल	तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	2	500	5-अक्तू.-15	5-अक्तू.-15	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	निजी	यूपीसीएल	उडुपी टीपीपी	1	600	10-अग.-15	10-सितं.-15	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	निजी	यूपीसीएल	उडुपी टीपीपी	2	600	11-अग.-15	27-अग.-15	कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	कर्नाटक	निजी	यूपीसीएल	उडुपी टीपीपी	2	600	19-अप्रैल-16		कच्चे पानी की समस्या
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	निजी	एचएनपीसी	विजग टीपीपी	1	520	2-फर.-16	2-फर.-16	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	महाराष्ट्र	निजी	ईईएल	एमको वरौरा टीपीएस	1	300	20-मई-15	26-मई-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	महाराष्ट्र	निजी	ईईएल	एमको वरौरा टीपीएस	1	300	15-अप्रैल-16		कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
पश्चिम क्षेत्र	महाराष्ट्र	निजी	ईईएल	एमको वरौरा टीपीएस	2	300	19-अप्रैल-16		कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर
पश्चिम क्षेत्र	छत्तीसगढ़	निजी	एसीबी	कसाईपल्ली टीपीपी	2	135	21-अग.-15	23-अग.-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	निजी	ईपीजीएल	सलाया टीपीपी	2	600	30-मार्च-15	7-अप्रैल-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	निजी	ईपीजीएल	सलाया टीपीपी	2	600	9-अप्रैल-15	9-मई-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	निजी	ईपीजीएल	सलाया टीपीपी	2	600	12-जुला.-15	24-जुला.-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	निजी	ईपीजीएल	सलाया टीपीपी	2	600	1-सितं.-15	14-सितं.-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	मध्य प्रदेश	निजी	एसपीएल	सासन यूएमटीपीपी	3	660	26-जुला.-15	27-जुला.-15	कच्चे पानी की समस्या
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	राज्य	जीएसईसीएल	सिक्का रिप. टीपीएस	3	250	27-अक्तू.-15	31-अक्तू.-15	कच्चा पानी उपलब्ध नहीं/नहर का कम इंटेक स्तर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-71

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

गैस-ग्रिड से संबद्ध विद्युत उत्पादन

71. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में मौजूद 24,150 मेगावाट गैस-ग्रिड संबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता में से 14,305 मेगावाट क्षमता के लिए वर्तमान में स्वदेशी गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है और इस कारण यह उत्पादन क्षमता स्थगित मानी जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गैस की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्तमान में देश गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए घरेलू गैस की उपलब्धता में कमी का सामना कर रहा है तथा अधिकांश गैस आधारित विद्युत संयंत्र बहुत कम संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर प्रचालनरत है।

देश में उपलब्ध स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 27.03.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या (ओएम) 4/2/2015-थर्मल-1 के तहत एक रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के जरिए चयनित लक्ष्य पीएलएफ तक उत्पादन के लिए स्ट्रैंडिड विद्युत संयंत्रों और घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों, दोनों को स्पॉट आरएलएनजी (ई-बोली आरएलएनजी) द्वारा देश में गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए एक योजना अधिसूचित की है।

इस योजना में सभी पणधारकों द्वारा किए जाने वाले अधित्याग तथा पीएसडीएफ सहायता की परिकल्पना भी की गई है। योजना के तहत उपलब्ध कराई गई रियायतें निम्नानुसार हैं:

- (i) आयातित एलएनजी पर सीमाशुल्कों का अधित्याग;
- (ii) मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर का अधित्याग;
- (iii) पुनः गैसीकरण एवं परिवहन पर सेवा कर का अधित्याग;
- (iv) पाइपलाइन प्रशुल्क प्रभारों, पुनः गैसीकरण प्रभारों तथा विपणन मार्जिन में कमी;
- (v) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रभारों तथा हानियों से छूट।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो वर्ष की अवधि के लिए वैध है। यह योजना 01 जून, 2015 से कार्यान्वयनाधीन है और इस योजना के तहत नीलामी के तीन दौर पूरे किए जा चुके हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-72

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

टीएनजीडीसी को आरईसी तथा पीएफसी द्वारा वित्तपोषण किया जाना

72. श्री सालिम अन्सारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) तथा विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) ऊर्जा मीटर खरीदने और अन्य विद्युत परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु जनरेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएनजीडीसी) को वित्तपोषण कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आरईसी एवं पीएफसी द्वारा टीएनजीडीसी को किए गए वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि टीएनजीडीसी लघु औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त माल का उनको भुगतान नहीं कर रहा है और वित्तीय हानि पहुंचा रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आरईसी, पीएफसी तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) ऊर्जा मीटरों सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टेंजेडको) को वित्तपोषण कर रहे हैं। आरईसी एवं पीएफसी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान टेंजेडको को स्वीकृति का ब्यौरा निम्नानुसार है।

रुपए करोड़ में

	2013-14	2014-15	2015-16
आरईसी	1369.88	1145.58	1213.67
पीएफसी	2843	3167	3669

(ग) और (घ) : आरईसी को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पीएफसी द्वारा प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए टीएनजीडीसी को अग्रेषित कर दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-73

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

लोक उद्यमों की वित्तीय स्थिति

73. श्री तपन कुमार सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2013, वर्ष 2014 तथा वर्ष 2015 के दौरान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, विद्युत वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की आरक्षित तथा अधिशेष पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार इन लोक उद्यमों के ऋण तथा इक्विटी का अनुपात क्या है;

(ग) इन लोक उपक्रमों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान कितना निवेश किया गया है; और

(घ) अगले तीन वर्षों के लिए निधीयन पद्धति सहित निवेश का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2013, 2014 और 2015 के दौरान पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) की आरक्षित तथा अधिशेष पूंजी निम्नवत है:

क्र.सं.	पीएसई का नाम	आरक्षित तथा अधिशेष पूंजी (रुपए करोड़ में)		
		2013	2014	2015
1.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	21,610.00	29,228.00	32,935.00
2.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी)	22,256.13	26,054.57	30,899.17
3.	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी)	16,466.92	19,682.00	23,869.57
4.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी)	15,539.76	14,996.98	17,215.72

(ख) : 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसई) का ऋण इक्विटी अनुपात निम्नवत है:

क्र.सं.	पीएसई का नाम	ऋण/इक्विटी अनुपात
1.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	2.47
2.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी)	6.29
3.	रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन (आरईसी)	6.08
4.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी)	0.64

(ग) : गत तीन वर्षों के दौरान इन पीएसई द्वारा किया गया निवेश निम्नवत है:

क्र.सं.	पीएसई का नाम	निवेश (रुपए करोड़ में)		
		2013	2014	2015
1.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	20,360.00	23,158.00	22,456.00
2.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) @	-	-	-
3.	रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) @	-	-	-
4.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी)	3,307.26	3,219.03	2,615.45

(घ) : अगले तीन वर्षों के लिए निवेश योजना निम्नवत है:

क्र.सं.	पीएसई का नाम	निवेश योजना (रुपए करोड़ में)		
		2016-17	2017-18	2018-19
1.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	22,500.00	20,000.00*	20,000.00*
		* अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, शुरु की जा चुकी परियोजनाओं तथा आंतरिक संसाधनों (आईआर) की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में निवेश 22,500.00 करोड़ रुपए तक जा सकता है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के प्रशुल्क विनियमों तथा आईआर की उपलब्धता की तर्ज पर उपर्युक्त निवेश योजना को 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।		
2.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) @	-	-	-
3.	रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) @	-	-	-
4.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी)	5,067.96	5,417.91	5,369.51
		70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ वित्त पोषित।		

@ आरईसी और पीएफसी विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के कार्य में लगे हुए वित्तीय संस्थान हैं। ये संस्थान परियोजनाओं में प्रत्यक्ष रूप से कोई पूंजीगत निवेश नहीं करते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-74

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है।

रामागुंडम स्थित एनटीपीसी इकाई की स्थिति

74. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तेलंगाना के रामागुंडम में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की इकाई की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या विशेषज्ञ अध्ययन समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह इकाई देश में सर्वाधिक प्रदूषक और अदक्ष इकाई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (घ) इस इकाई के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार की क्या योजना है; और
- (ङ) विभिन्न इकाइयों से तेलंगाना को सरकार द्वारा यूनिट-वार तथा धनराशि-वार कितनी-कितनी विद्युत आवंटित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी रामागुंडम स्टेशन की संस्थापित क्षमता 2600 मेगावाट (3x200 + 4x500 मेगावाट) है। रामागुंडम सोलर की संस्थापित क्षमता 10 मेगावाट है। सभी यूनिटें प्रचालन में हैं। इसके अतिरिक्त, रामागुंडम परियोजना परिसर में 2x800 मेगावाट तेलंगाना फेज-I का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन अधिकृत नहीं किया है।

(घ) : एनटीपीसी रामागुंडम एक उच्च निष्पादन करने वाला केंद्र है जो वर्ष 2015-16 में 88% से अधिक पीएलएफ पर प्रचालन कर रहा है। यह सभी सांविधिक और पर्यावरणीय अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। तथापि, निष्पादन में और सुधार करने के लिए स्टेज-I यूनिटों (3x200 मेगावाट), जिन्होंने 25 वर्षों का जीवनकाल पूर्ण किया है, का नवीनीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

(ङ) : अनावंटित विद्युत सहित एनटीपीसी की ऐसी यूनिटों से तेलंगाना राज्य को चालू आबंटन निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	तेलंगाना को आबंटन (मेगावाट)
1	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-I व II	357.74
2	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-III	89.68
3	रामागुंडम सोलर	5.39

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-75

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

उत्तराखंड में उपगांवों का विद्युतीकरण

75. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि धनराशि की कमी के कारण उत्तराखंड की हजारों ग्राम सभाओं के उपगांवों का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ग) क्या इस राज्य की ग्राम सभाओं के उपगांवों के विद्युतीकरण हेतु मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराई जाएगी; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान उत्तराखंड सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। वर्ष 2015-16 के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 845.30 करोड़ रु. संस्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 71.21 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-76

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

नए विद्युत संयंत्र

76. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में नए विद्युत संयंत्र लगाने तथा बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं देश में चौबीस घंटे बिजली देने का संकल्प लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कहां-कहां पर ये संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है एवं बिहार में कितने स्थानों पर ये संयंत्र लगाए जाएंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी हाँ। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परंपरागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की तुलना में 31.03.2016 तक 84,990.7 मेगावाट हासिल कर ली गई है। 2012-16 के दौरान परंपरागत स्रोतों में चालू की गई नई विद्युत परियोजनाओं की सूची अनुबंध-I में दी गई है। 2016-17 के लिए नियोजित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की सूची, जिसमें बिहार राज्य में परियोजनाएं शामिल हैं, अनुबंध-II में दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार) चालू की गई परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की वर्ष
1	इंदिरा गांधी (झज्जर) एसटीपीपी यू-3	हरियाणा	केंद्रीय	कोयला	500	2012-13
2	कोडरमा टीपीपी यूनिट-2	झारखंड	केंद्रीय	कोयला	500	2012-13
3	मौदा टीपीपी यू-1,2	महाराष्ट्र	केंद्रीय	कोयला	1000	2012-13
4	विंध्याचल एसटीपीएस-IV यू-11,12	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	1000	2012-13
5	वल्लूर टीपीपी फेज-1 यूनिट 2	तमिलनाडु	केंद्रीय	कोयला	500	2012-13
6	रिहंद एसटीपीपी स्टे.-III यूनिट-5	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	500	2012-13
7	सिपत स्टे.-I एसटीपीपी यूनिट-3	छत्तीसगढ़	केंद्रीय	कोयला	660	2012-13
8	बाढ़ एसटीपीपी-II यू-2	बिहार	केंद्रीय	कोयला	660	2013-14
9	वल्लूर टीपीपी यूनिट-3	तमिलनाडु	केंद्रीय	कोयला	500	2013-14
10	रिहंद एसटीपीएस स्टे.-III यू-6	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	500	2013-14
11	मुजफ्फरपुर यू-3	बिहार	केंद्रीय	कोयला	195	2014-15
12	बाढ़ एसटीपीपी स्टे.-II यू-5	बिहार	केंद्रीय	कोयला	660	2014-15
13	तूतीकोरिन जेवी यू-1	तमिलनाडु	केंद्रीय	कोयला	500	2014-15
14	एनएलसी टीपीपी-2 एक्सपें. यू-2	तमिलनाडु	केंद्रीय	कोयला	250	2014-15
15	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-1	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	कोयला	600	2014-15
16	बोंगाईगांव टीपीपी यू-1	असम	केंद्रीय	कोयला	250	2015-16
17	नबी नगर टीपीपी एक्सपें. यू-1	बिहार	केंद्रीय	कोयला	250	2015-16
18	बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें. यू-1	झारखंड	केंद्रीय	कोयला	500	2015-16
19	मौदा एसटीपीपी-II यू-3	महाराष्ट्र	केंद्रीय	कोयला	660	2015-16
20	विंध्याचल एसटीपीपी स्टे.-V यू-13	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	500	2015-16
21	तूतीकोरिन जेवी यू-2	तमिलनाडु	केंद्रीय	कोयला	500	2015-16
22	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-1 यू-2	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	कोयला	600	2015-16
23	त्रिपुरा सीसीजीटी	त्रिपुरा	केंद्रीय	गैस	363.3	2012-13
24	अगरतला सीसीपीपी स्टे.-I	त्रिपुरा	केंद्रीय	गैस	25.5	2014-15
25	मोनार्चक सीसीपीपी	त्रिपुरा	केंद्रीय	गैस	65.4	2014-15
26	त्रिपुरा सीसीजीटी, ब्लॉक-2	त्रिपुरा	केंद्रीय	गैस	363.3	2014-15
27	त्रिपुरा सीसीजीटी, मोनार्चक	त्रिपुरा	केंद्रीय	गैस	35.6	2015-16
28	चमेरा-III यूनिट 1,2,3	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	231	2012-13
29	चूटक एचईपी यूनिट-1,2,3,4	जम्मू व कश्मीर	केंद्रीय	हाइड्रो	44	2012-13
30	तीस्ता लो डैम-III यूनिट-1,2,3	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	हाइड्रो	99	2012-13
31	पारबती-III यू-1-3	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	390	2013-14
32	रामपुर एचईपी यू-1,2,5	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	206.01	2013-14
33	उरी एचईपी यू-1-4	जम्मू व कश्मीर	केंद्रीय	हाइड्रो	240	2013-14
34	निम्मो बाजगो एचईपी यू-1-3	जम्मू व कश्मीर	केंद्रीय	हाइड्रो	45	2013-14
35	तीस्ता लो डैम-III एचईपी यू-4	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	हाइड्रो	33	2013-14
36	पारबती-III एचईपी यू-4	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	130	2014-15
37	रामपुर एचईपी यू-3,4,6	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	206.01	2014-15
38	कोलडैम एचईपी यू-1,2	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	400	2014-15
39	कोलडैम यू-3,4	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	400	2015-16
40	तीस्ता लो डैम स्टेज-IV यू-1,2	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	हाइड्रो	80	2015-16

41	कुडनकुलम यू-1	तमिलनाडु	केंद्रीय	न्यूक्लियर	1000	2014-15
42	कोरबा वेस्ट	छत्तीसगढ़	राज्य	कोयला	500	2012-13
43	उकई टीपीपी एक्सटें. यू-6	गुजरात	राज्य	कोयला	500	2012-13
44	सतपुरा टीपीएस एक्सटें. यू-10	मध्य प्रदेश	राज्य	कोयला	250	2012-13
45	मेदूर टीपीपी एक्सटें. यू-1	तमिलनाडु	राज्य	कोयला	600	2012-13
46	नॉर्थ चेन्नई एक्सटें. यू-2	तमिलनाडु	राज्य	कोयला	600	2012-13
47	हरदुआगंज टीपीपी एक्सटें. यूनिट-9	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	250	2012-13
48	परीछा एक्सटें. यू-5,6	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	500	2012-13
49	मारवा टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	राज्य	कोयला	500	2013-14
50	श्री सिंगाजी टीपीपी यू-1	मध्य प्रदेश	राज्य	कोयला	600	2013-14
51	सतपुरा टीपीपी यू-11	मध्य प्रदेश	राज्य	कोयला	250	2013-14
52	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें. यू-3	राजस्थान	राज्य	कोयला	250	2013-14
53	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस स्टे.-II यू-1	तमिलनाडु	राज्य	कोयला	600	2013-14
54	दुर्गापुर टीपीपी एक्सटें. यू-1	पश्चिम बंगाल	राज्य	कोयला	250	2013-14
55	दामोदर संजीव्याह टीपीएस यू-1,2	आंध्र प्रदेश	राज्य	कोयला	1600	2014-15
56	सिक्का टीपीपी एक्सटें. यू-3	गुजरात	राज्य	कोयला	250	2014-15
57	चंद्रपुर यू-8	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	500	2014-15
58	कोराडी टीपीएस एक्सटें. यू-8	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	660	2014-15
59	श्री सिंगाजी टीपीपी यू-2	मध्य प्रदेश	राज्य	कोयला	600	2014-15
60	कालीसिंध टीपीपी यू-1	राजस्थान	राज्य	कोयला	600	2014-15
61	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें. यू-4	राजस्थान	राज्य	कोयला	250	2014-15
62	सिक्का टीपीएस एक्सटें. यू-4	गुजरात	राज्य	कोयला	250	2015-16
63	बेल्लारी टीपीपी स्टे.-III यू-3	कर्नाटक	राज्य	कोयला	700	2015-16
64	येरमारस टीपीपी यू-1	कर्नाटक	राज्य	कोयला	800	2015-16
65	चंद्रपुर टीपीएस एक्सटें. यू-9	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	500	2015-16
66	कोराडी टीपीएस एक्सटें. यू-9	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	660	2015-16
67	पार्ली टीपीएस यू-8	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	250	2015-16
68	कालीसिंध एसटीपीपी यू-2	राजस्थान	राज्य	कोयला	600	2015-16
69	काकातिया टीपीपी स्टे.-II यू-1	तेलंगाना	राज्य	कोयला	600	2015-16
70	सिंगारेनी टीपीपी यू-1	तेलंगाना	राज्य	कोयला	600	2015-16
71	अनपरा डी टीपीपी यू-6,7	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	1000	2015-16
72	सागरदिघी टीपीपी एक्सटें. यू-3	पश्चिम बंगाल	राज्य	कोयला	500	2015-16
73	पीपावाव सीसीपीपी	गुजरात	राज्य	गैस	351	2012-13
74	रामगढ़ जीटी	राजस्थान	राज्य	गैस	110	2012-13
75	प्रगति-III जीटी-3	दिल्ली	राज्य	गैस	250	2012-13
76	प्रगति-III जीटी-4, स्टे.-2	दिल्ली	राज्य	गैस	500	2013-14
77	पीपावाव सीसीपीपी ब्लॉक-1	गुजरात	राज्य	गैस	351	2013-14
78	रोखिया जीटी	त्रिपुरा	राज्य	गैस	21	2013-14
79	धुवरन सीसीपीपी-III	गुजरात	राज्य	गैस	376.1	2014-15
80	रामगढ़ एसटी	राजस्थान	राज्य	गैस	50	2014-15
81	मिंटू यू-3	मेघालय	राज्य	हाइड्रो	42	2012-13
82	भवानी कट्टलई बैराज-III यू-1	तमिलनाडु	राज्य	हाइड्रो	15	2012-13
83	भवानी कट्टलई बैराज-II यू-1-2	तमिलनाडु	राज्य	हाइड्रो	30	2013-14
84	भवानी कट्टलई बैराज-III यू-2	तमिलनाडु	राज्य	हाइड्रो	15	2013-14
85	बगलीहार स्टेज-II यू-1,2	जम्मू व कश्मीर	राज्य	हाइड्रो	300	2015-16
86	बगलीहार स्टेज-II यू-3	जम्मू व कश्मीर	राज्य	हाइड्रो	150	2015-16
87	लोअर जुराला यू-1,2,3,4	तेलंगाना	राज्य	हाइड्रो	160	2015-16
88	थामिनापट्टनम टीपीपी-1 यू-1	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150	2012-13
89	कसाईपल्ली टीपीएस यूनिट-2	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	135	2012-13
90	रतीजा टीपीपी यूनिट-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	50	2012-13
91	सलाया टीपीएस यू-2	गुजरात	निजी	कोयला	600	2012-13
92	यूएमपीपी मुंद्रा यू-2,3,4,5	गुजरात	निजी	कोयला	3200	2012-13
93	महात्मा गांधी टीपीपी यू-2	हरियाणा	निजी	कोयला	660	2012-13

94	आधुनिक पावर टीपीपी यू-1,2	झारखंड	निजी	कोयला	540	2012-13
95	अमरावती टीपीपी फेज-1 यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	270	2012-13
96	बेला टीपीपी-1 यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	270	2012-13
97	बुटीबोरी टीपीपी यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300	2012-13
98	एमको वरौरा टीपीपी यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300	2012-13
99	जीईपीएल टीपीपी फेज-1, यूनिट-1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	120	2012-13
100	तिरौरा टीपीपी फेज-1 यू-1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	1320	2012-13
101	बीना टीपीपी यू-1,2	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	500	2012-13
102	महान टीपीपी यूनिट-1	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	600	2012-13
103	स्टरलाइट (झारसुगडा) टीपीपी यू-4	ओडिशा	निजी	कोयला	600	2012-13
104	कमलंगा टीपीपी यू-1	ओडिशा	निजी	कोयला	350	2012-13
105	इंड बराथ तूतीकोरिन यू-1	तमिलनाडु	निजी	कोयला	150	2012-13
106	सिम्हापुरी टीपीपी फेज-1 यू-2	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150	2012-13
107	थामिनापट्टनम टीपीपी यू-2	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150	2013-14
108	सिम्हापुरी टीपीपी यूनिट-3	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150	2013-14
109	अकलतारा नैयारा टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	600	2013-14
110	बाराधरा टीपीपी यूनिट-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	600	2013-14
111	तमनार टीपीपी यू- (रायगढ़)	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	600	2013-14
112	चकाबुरा टीपीपी	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	30	2013-14
113	अवंथा भंडार टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	600	2013-14
114	तमनार टीपीपी यू-2 (रायगढ़)	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	600	2013-14
115	टिरोडा टीपीपी फेज-II यू-1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	1320	2013-14
116	एमको वरौरा टीपीपी यू-2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300	2013-14
117	धारीवाल टीपीपी, यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300	2013-14
118	मरावती टीपीपी, फेज-1, यूनिट 2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	270	2013-14
119	नासिक टीपीपी, फेज-1, यूनिट 1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	270	2013-14
120	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II यू-2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300	2013-14
121	सासन यूएमपीपी यू-1	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	660	2013-14
122	सासन यूएमपीपी यू-2,4	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	1320	2013-14
123	निवारी टीपीपी यू-1	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	45	2013-14
124	कमलंगा टीपीपी यू-2,3	ओडिशा	निजी	कोयला	700	2013-14
125	राजपुरा टीपीपी यू-1	पंजाब	निजी	कोयला	700	2013-14
126	कवाई टीपीपी यू-1,2	राजस्थान	निजी	कोयला	1320	2013-14
127	इंड बराथ तूतीकोरिन यू-2	तमिलनाडु	निजी	कोयला	150	2013-14
128	पैनमपुरम टीपीपी यू-1	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	660	2014-15
129	सिम्हापुरी फेज-II यू-4	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150	2014-15
130	स्वास्तिक कोरबा यू-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	25	2014-15
131	अकलतारा (नैतारा) टीपीपी	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	600	2014-15
132	तमनार टीपीपी यू-3,4	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	1200	2014-15
133	राइखेडा टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	685	2014-15
134	सलोरा टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	135	2014-15
135	बारादरहा यू-2	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	600	2014-15
136	धारीवाल टीपीपी यू-2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300	2014-15
137	तिरौरार टीपीपी, फेज-II यूनिट-3	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	660	2014-15
138	अमरावती टीपीपी फेज-1 यू-3,4,5	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	810	2014-15
139	सासन यूएमपीपी यू-3,5,6	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	1980	2014-15
140	निगरी टीपीपी यू-1,2	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	1320	2014-15
141	देरांग टीपीपी यू-1,2	ओडिशा	निजी	कोयला	1200	2014-15
142	तलवंडी साबो टीपीपी यू-1	पंजाब	निजी	कोयला	660	2014-15
143	राजपुरा टीपीपी यू-2	पंजाब	निजी	कोयला	700	2014-15
144	मुतियारा टीपीपी यू-1	तमिलनाडु	निजी	कोयला	600	2014-15
145	हल्दिया टीपीपी यू-1, 2	पश्चिम बंगाल	निजी	कोयला	600	2014-15
146	पैनमपुरम टीपीपी यू-2	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	660	2015-16

147	विजग टीपीपी यू-1, 2	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	1040	2015-16
148	बंदाखार टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	300	2015-16
149	बाल्को टीपीपी यू-1,2	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	600	2015-16
150	उचपिंडा टीपीपी, यू-1,2	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	720	2015-16
151	राइखेड़ा टीपीपी यू-2	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	685	2015-16
152	अनूपपुर टीपीपी यू-1,2	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	1200	2015-16
153	सिओनी टीपीपी फेज-I यू-1	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	600	2015-16
154	इंड बराथ एनर्जी प्रा. लि. टीपीपी यू-1	ओडिशा	निजी	कोयला	350	2015-16
155	तलवंडी साबो यू-2,3	पंजाब	निजी	कोयला	1320	2015-16
156	गोइंदवाल साहिब टीपीपी यू-1,2	पंजाब	निजी	कोयला	540	2015-16
157	आईटीपीसीएल टीपीपी यूनिट-I	तमिलनाडु	निजी	कोयला	600	2015-16
158	मुत्तियारा टीपीपी, यू-2	तमिलनाडु	निजी	कोयला	600	2015-16
159	प्रयागराज (बारा) टीपीपी U-I	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	660	2015-16
160	ललितपुर टीपीपी यू-1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	1320	2015-16
161	युनोसुजैन सीसीपीपी मॉड्यूल-1	गुजरात	निजी	गैस	382.5	2012-13
162	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी, मॉड्यूल 1,2	गुजरात	निजी	गैस	800	2013-14
163	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी मॉड्यूल 3	गुजरात	निजी	गैस	400	2014-15
164	कोंडापल्ली स्टेज-III-ए (यू-1,2)	आंध्र प्रदेश	निजी	गैस	742	2015-16
165	जीएमआर रामजमुंदरी एनर्जी लि., ब्लॉक-1, 2	आंध्र प्रदेश	निजी	गैस	768	2015-16
166	जलीपा कपूर्दी यू-5,6,7,8	राजस्थान	निजी	लिग्नाइट	540	2012-13
167	बुधहिल यूनिट-1,2	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	70	2012-13
168	चूजैचान एचईपी यू-1,2	सिक्किम	निजी	हाइड्रो	99	2013-14
169	जोरथांग लूप यू-1,2	सिक्किम	निजी	हाइड्रो	96	2015-16
170	श्रीनगर यू-1,2,3,4	उत्तराखंड	निजी	हाइड्रो	330	2015-16
				कुल	84990.72	

राज्य सभा में दिनांक 25.04.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2016-17 के लिए अनंतिम उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य

राज्य	परियोजना	विकासकर्ता	यूनिट	ईंधन	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र					
बिहार	नबीनगर टीपीपी,	एनटीपीसी	2	थर्मल	250
बिहार	कांती टीपीएस स्ट.-II	एनटीपीसी	4	थर्मल	195
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	4	थर्मल	660
छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी	एनटीपीसी	1	थर्मल	800
कर्नाटक	कुडगी टीपीपी	एनटीपीसी	1	थर्मल	800
त्रिपुरा	अगरतला गैस आधारित विद्युत परियोजना	नीपको	एसटी-1	थर्मल	25.5
पश्चिम बंगाल	तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी	3	हाइड्रो	40
पश्चिम बंगाल	तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी	4	हाइड्रो	40
अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	नीपको	1	हाइड्रो	150
अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	नीपको	2	हाइड्रो	150
अरुणाचल प्रदेश	पारे	नीपको	1	हाइड्रो	55
अरुणाचल प्रदेश	पारे	नीपको	2	हाइड्रो	55
तमिलनाडु	कुडनकुलम एनपीपी	एनपीसी	2	न्यूक्लियर	1000
तमिलनाडु	पीएफबीआर कलपक्कम	भाविनी	1	न्यूक्लियर	500
राज्य क्षेत्र					
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	जीटी+एसटी	थर्मल	100
बिहार	बराँनी टीपीपी,	बीएसईबी	8	थर्मल	250
गुजरात	भावनगर टीपीपी	बीईसीएल	1	थर्मल	250
गुजरात	भावनगर टीपीपी	बीईसीएल	2	थर्मल	250
कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	केपीसीएल	2	थर्मल	800
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी	एमएसपीजीसीएल	10	थर्मल	660
तेलंगाना	सिंगरैनी टीपीपी	एससीसीएल	2	थर्मल	600
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीएस	सीएसपीजीसीएल	2	थर्मल	500
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीएस-II	पश्चिम बंगाल पीडीसीएल	4	थर्मल	500
आंध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर टीआर	एपजैको	1	हाइड्रो	25
आंध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर टीआर	एपजैको	2	हाइड्रो	25
हिमाचल प्रदेश	कशांग-I	एचपीपीसीएल	1	हाइड्रो	65
हिमाचल प्रदेश	सैंज	एचपीपीसीएल	1	हाइड्रो	50
हिमाचल प्रदेश	सैंज	एचपीपीसीएल	2	हाइड्रो	50
तेलंगाना	लोअर जुराला	टीएसजैको	5	हाइड्रो	40
तेलंगाना	लोअर जुराला	टीएसजैको	6	हाइड्रो	40
तेलंगाना	पुलीचिंताला	टीएसजैको	1	हाइड्रो	30
तेलंगाना	पुलीचिंताला	टीएसजैको	2	हाइड्रो	30
मेघालय	न्यू उमतरू	एमईपीजीसीएल	1	हाइड्रो	20
मेघालय	न्यू उमतरू	एमईपीजीसीएल	2	हाइड्रो	20

निजी क्षेत्र					
छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी	टीआरएन	1	थर्मल	300
छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी	टीआरएन	2	थर्मल	300
उत्तर प्रदेश	बारा टीपीपी	जेपी	2	थर्मल	660
ओडिशा	उत्कल टीपीपी	इंड बराथ	2	थर्मल	350
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	आरकेएम	3	थर्मल	360
तमिलनाडु	आईटीपीसीएल टीपीपी	आएलएफएस	2	थर्मल	600
ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी	लैंको बाबंध	1	थर्मल	660
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	एलपीजीसीएल	3	थर्मल	660
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी, फेज-1	रत्तन पावर	2	थर्मल	270
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी, फेज-1	रत्तन पावर	3	थर्मल	270
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी	1	थर्मल	660
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी	2	थर्मल	660
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	एसकेएस	1	थर्मल	300
छत्तीसगढ़	एथेना सिंघीतराई टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़	1	थर्मल	600
पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी	इंडिया पावर	1	थर्मल	150
सिक्किम	तीस्ता-III (*)	तीस्ता ऊर्जा लि.	1	हाइड्रो	200
सिक्किम	तीस्ता-III (*)	तीस्ता ऊर्जा लि.	2	हाइड्रो	200
सिक्किम	तीस्ता-III (*)	तीस्ता ऊर्जा लि.	3	हाइड्रो	200
हिमाचल प्रदेश	चंजू-1	आईए एनर्जी	1	हाइड्रो	12
हिमाचल प्रदेश	चंजू-1	आईए एनर्जी	2	हाइड्रो	12
हिमाचल प्रदेश	चंजू-1	आईए एनर्जी	3	हाइड्रो	12
सिक्किम	दिक्चू	स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	1	हाइड्रो	32
सिक्किम	दिक्चू	स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	2	हाइड्रो	32
सिक्किम	दिक्चू	स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	3	हाइड्रो	32
सिक्किम	ताशिडिंग	शिगा एनर्जी प्रा. लि.	1	हाइड्रो	48.5
सिक्किम	ताशिडिंग	शिगा एनर्जी प्रा. लि.	2	हाइड्रो	48.5
				अखिल भारत	16654.5
(*) 6 अगस्त, 2015 से तीस्ता ऊर्जा लि. सिक्किम सरकार का उद्यम है।					

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-77

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है।

डिस्कॉम के ऋण

77. श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सितम्बर, 2015 तक डिस्कॉम को कुल 3.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;
- (ख) क्या उक्त अवधि तक डिस्कॉम का कुल बकाया ऋण बढ़कर 4.3 लाख करोड़ रुपये तक हो गया है;
- (ग) क्या विगत छह वर्षों के दौरान डिस्कॉम का कुल नुकसान 3.66 लाख करोड़ रुपये हो गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की संचयी हानियां 3,18,345 करोड़ रुपए थीं और कुल बकाया ऋण 3,75,344 करोड़ रुपए था। विगत तीन वर्षों के रुझानों के आधार पर वर्ष 2014-15 के लिए 55,000 करोड़ रुपए की हानियां अनुमानित की गई थीं।

(ग) और (घ) : 2008-09 से 2013-14 तक प्राप्त सब्सिडी के आधार पर डिस्कॉमों की हानियां 3,40,968 करोड़ रुपए थीं। वर्ष-वार आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:

(रुपए करोड़ में)

	प्राप्त सब्सिडी आधार पर हानि
2008-09	34,811
2009-10	41,558
2010-11	51,971
2011-12	76,877
2012-13	71,690
2013-14	64,060
कुल	3,40,968

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-78

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है ।

‘उदय’ के अन्तर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

78. श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शीघ्र लाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) क्या उक्त समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत बिजली की चोरी, मीटर के साथ छेड़छाड़ आदि के लिए डिस्कॉम के कर्मचारी उत्तरदायी होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नएराउंड के लिए 20.11.2015 को पहले से ही उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) शुरू कर दी है।

(ख) : अब तक 10 राज्यों ने अपने डिस्कॉमों सहित विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) और (घ) : समझौता ज्ञापन में अन्य उपायों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि डिस्कॉम विद्युत चोरी पर नियंत्रण करने, हानि में कमी लाने के लक्ष्यों को तैयार करने, निष्पादन निगरानी को कार्यान्वित करने, मीटर बदलने को ट्रैक करने, हानि में कमी लाने और अधिकारी के निष्पादन का मूल्यांकन के लिए की परफॉरमेंस इंडिकेटर (केपीआईएस) युक्ति तैयार करने के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे।
